रावुला सुब्बा राव और एक और

बनाम

आय-कर आयोग, मद्रास

[एस. आर. दास सी. जे., भगवती और वेंकटरामा अय्यर जे.)

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का अधिनियम 11), 26-ए; 69, नियमों में धारा 69-शब्द 'व्यक्तिगत रूप से' के तहत बनाए गए नियम 2 और 6 क्या एक विधिवत अधिकृत एजेंट को भागीदार की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने से बाहर करता है। धारा 26 ए-नियम 2 और 6 के तहत क्या नियम बनाने वाले प्राधिकरण-भारतीय आयकर अधिनियम, 1922-के अधिकार क्षेत्र से बाहर है-क्या उसमें निपटाए गए मामलों का विस्तृत विवरण है।

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 59 के तहत बनाए गए नियमों के नियम 2 और 6 में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 26-ए के तहत किसी फर्म के पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर सभी पक्षों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 59 के तहत बनाए गए आयकर नियमों में 'व्यक्तिगत रूप से' शब्द, आयकर अधिनियम की धारा 26-ए के तहत भागीदार की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले फर्म के भागीदार के विधिवत अधिकृत एजेंट को बाहर कर देगा।

(2) वह नियम 2 और 6 नियम बनाने वाले प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं।

इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए कि क्या भारतीय आयकर अधिनियम की सही व्याख्या के आधार पर यह अभिप्रेत है कि धारा 26-क के तहत एक आवेदन पर भागीदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, या क्या उस पर उसके प्रतिनिधि द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, न्यायालय को न केवल धारा 26-क की भाषा, बल्कि विधान के स्वरूप, अधिनियम की योजना और धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार की प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए।

भारतीय आयकर अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है जिसमें उन मामलों को शामिल किया गया है जिनसे निपटा गया है और इसके प्रावधान सामान्य नियम से अलग होने का इरादा दर्शाते हैं। इसका इरादा फिर से यह है कि किसी फर्म को धारा 23 (5) (ए) का लाभ केवल तभी दिया जाना चाहिए जब वह उस धारा में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार धारा 26-ए के तहत पंजीकृत हो। और चूंकि उन नियमों के अनुसार आवेदन पर भागीदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी ओर से एक एजेंट द्वारा हस्ताक्षर वैध है।

कृषि आय-कर आयुक्त बनाम केशा-बी चंद्र मंडल, ([1950] एस. सी. आर. 435), पर भरोसा किया।

आय-कर आयुक्त बनाम सुब्बा राव, (1947) आई. एल. आर. मैड। 167) स्वीकृत।

संदर्भित अन्य मामला-कानून।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 1954 की सिविल अपील संख्या 56 और 57।

1948 की सं. 32 और 1950 की सं. 31 में संदर्भित मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के 25 मार्च, 1951 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थियों के लिए के. एस. कृष्णस्वामी अयंगर, (के. आर. चौधरी, उनके साथ)।

जी, एन. जोशी और पी.-जी. गोखले, प्रत्यर्थी के लिए।

9 मई 1956 को न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

वेंकटरामा अय्यर J.- अपीलार्थी एक फर्म है जिसका गठन दिनांक 10-2-1941 के साझेदारी विलेख के तहत किया गया था, और इसमें दो भागीदार, सुब्बा राव और हरिप्रसाद राव शामिल हैं। 21-3-1942 पर इसे भारतीय आयकर अधिनियम सं. 26-ए की धारा के तहत पंजीकृत किया

गया था, 11 (1922) जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे वर्ष 1942 के लिए निर्धारण किया गया । इसके कुछ समय बाद, कहा जाता है कि भागीदारों में से एक, सुब्बा राव, एक लंबी तीर्थयात्रा पर चले गए थे, और साझेदारी के मामलों का प्रबंधन हरिप्रसाद राव द्वारा उनके एजेंट के रूप में एक सामान्य पावर-ऑफ-अटॉर्नी दिनांक 1-7-1940 के तहत किया गया था। हरिप्रसाद राव ने तब अधिनियम की धारा 59 के तहत बनाए गए नियमों के नियम 2 और 6 के तहत आवेदन किया, वर्ष 1942-43 के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए, और आवेदन पर उनके द्वारा और फिर से सुब्बा राव के वकील के रूप में हस्ताक्षर किए गए। उन नियमों में प्रावधान है कि धारा 26-ए के तहत एक फर्म के पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन "सभी भागीदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा"। आयकर अधिकारी ने नवीनीकरण के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें भागीदारों में से एक, सुब्बा राव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और उनके एजेंट के रूप में हरिप्रसाद राव के हस्ताक्षर वैध नहीं थे। आदेश अपील में लिया गया था, और अंततः अधिनियम की धारा 66 (1) के तहत मद्रास उच्च न्यायालय को एक संदर्भ का विषय था, जिसमें कहा गया था कि नियम 6 में "व्यक्तिगत रूप से" शब्द के लिए आवश्यक है कि भागीदार को स्वयं आवेदन पर हस्ताक्षर करना चाहिए, और सामान्य कानून के तहत एजेंसी के सिद्धांतों को बाहर रखा गया था। (आयकर आयुक्त बनाम सुब्बा राव (1) के माध्यम से)।

जबकि ये कार्यवाही लंबित थी, हरिप्रसाद राव ने दो आवेदन दायर किए, जिनमें से वर्तमान अपीलें उत्पन्न होती हैं, मूल्यांकन वर्षों 1943-44 और 1944-45 के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए। उन दोनों पर उन्होंने अपने लिए और सुब्बा राव के वकील के रूप में हस्ताक्षर किए थे। इन याचिकाओं की सुनवाई में अपीलार्थी ने यह बनाए रखने के अलावा कि नियम 2 और 6, उनके वास्तविक निर्माण पर, एक भागीदार की ओर से एक एजेंट द्वारा हस्ताक्षर को बाहर नहीं किया, एक और तर्क उठाया कि नियम स्वयं नियम बनाने वाले प्राधिकरण की शक्तियों से परे थे। आयकर अधिकारी ने इन दोनों दलीलों को खारिज कर दिया, और आवेदनों को खारिज कर दिया, और अपीलीय सहायक आयुक्त और फिर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील पर उनके आदेशों की पुष्टि की गई। इसके बाद, अपीलार्थी के आवेदन पर, न्यायाधिकरण ने उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को भेजाः

"(1) क्या आयकर अधिनियम की धारा 59 के तहत बनाए गए आयकर नियमों में 'व्यक्तिगत रूप से' शब्द, आयकर अधिनियम की धारा 26 ए के तहत भागीदार की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने से भागीदार के विधिवत अधिकृत एजेंट को बाहर कर देगा?
(2) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या नियम 2 और 6 नियम बनाने वाले प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं?

इस संदर्भ को सत्यनारायण राव और विश्वनाथ शास्त्री, जे. जे. ने सुना। आय-कर आयुक्त बनाम सुब्बाराव (1) निर्णय के बाद मे उन्होने पहले सवाल का जवाब हां में दिया। लेकिन, दूसरे सवाल पर वे अलग थे। जे. सत्यनारायण राव ने अभिनिर्धारित किया कि नियम अधिकार से बाहर थे और आवेदन क्रम में थे और उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए थी। विश्वनाथ शास्त्री, जे. की राय इसके विपरीत थी, और उनका मानना था कि नियम अधिकार के भीतर थे, और आवेदनों को उनके अनुसार नहीं होने के कारण उचित रूप से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीशों ने अधिनियम की धारा 66-ए के तहत एक प्रमाण पत्र प्रदान किया, और इस तरह अपीलें हमारे सामने आती हैं।

पहला सवाल कि क्या "व्यक्तिगत रूप से" शब्द भागीदार की ओर से एक अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षर को बाहर कर देगा, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आयकर आयुक्त बनाम सुब्बा राव (1) मामले में सकारात्मक जवाब दिया गया था। यह कृषि आय-कर आयुक्त बनाम केशव चंद्र मंडल (2) में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत निर्णयों में से एक था, जहां सवाल यह था कि क्या बंगाल कृषि आय-कर अधिनियम के तहत बनाया गया एक नियम कि वापसी में घोषणा व्यक्ति द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित की जानी चाहिए, यह आवश्यक था कि उसे व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने चाहिए, और यह माना गया कि ऐसा करने की आवश्यकता थी। अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री के. एस. कृष्णस्वामी अय्यंगार ने उपरोक्त निष्कर्ष से भिन्न होने के लिए किसी भी आधार का आग्रह नहीं किया, और इसलिए हमें उपरोक्त निर्णयों में व्यक्त विचारों के साथ सहमति में यह मानना चाहिए कि नियमों द्वारा निर्धारित हस्ताक्षर स्वयं भागीदार के हैं, और उनकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले एजेंट द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता है।
फिर हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं-और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस अपील में हमारे निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है-क्या नियम 2 और 6 नियम बनाने वाले प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अपने इस तर्क के

समर्थन में अपीलार्थी का तर्क कि नियम अधिकार से बाहर हैं, इस प्रकार कहा जा सकता हैः इंग्लैंड के सामान्य कानून के तहत, एक व्यक्ति को एक एजेंट के माध्यम से वह करने का अधिकार है जो वह खुद कर सकता है, और वह अधिकार भी इस देश में उसे 1882 के पावर-ऑफ-अटॉर्नी एक्ट VII की धारा 2 द्वारा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार हैः
"अधिवक्ता का कर्ता, यदि वह उचित समझता है, तो मुख्तारनामा के प्राधिकरण द्वारा अपने नाम और हस्ताक्षर के साथ और अपनी मुहर के साथ किसी भी आश्वासन, उपकरण या चीज़ को निष्पादित या कर सकता है, और इस तरह से निष्पादित और किया गया प्रत्येक आश्वासन, उपकरण और चीज़ कानूनी रूप से उतना ही प्रभावी होगा जैसे कि इसे दाता के नाम पर मुख्तारनामा द्वारा निष्पादित या किया गया था, और उसके हस्ताक्षर और मुहर के साथ। "
यह धारा इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में निष्पादित उपकरणों द्वारा बनाई गई अधिवक्ता की शक्तियों पर लागू होती है।"
अधिनियम की धारा 26-ए एक भागीदार को फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान करती है, और उस अधिकार का प्रयोग एक अधिकृत एजेंट के माध्यम से सामान्य कानून और पावर ऑफ अटॉर्नी अधिनियम की धारा 2 दोनों के तहत किया जा सकता है। संप्रभु विधायिका, यदि वह ऐसा चाहे तो, सामान्य कानून के शासन को निरस्त कर सकती है, और पावर ऑफ अटॉर्नी अधिनियम की धारा 2 को निरस्त कर सकती है, और यह अधिनियमित कर सकती है कि धारा 26-ए के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पर स्वयं भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा; लेकिन उसने ऐसा स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से नहीं किया है, और इसलिए, जिस आवेदन पर हरिप्रसाद राव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, वह उतना ही अच्छा है जितना कि उस पर सुब्बा राव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नियमों में कोई संदेह नहीं है कि हस्ताक्षर भागीदार के होने चाहिए न कि उसके एजेंट के। लेकिन धारा के तहत जो वैध होगा उसे प्रतिबंधित करने में, नियम नियम बनाने वाले प्राधिकरण को धारा 26-ए द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के दायरे से परे जाते हैं, जो कानून में निर्धारित सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने तक सीमित है। इसलिए वे पराधिकार हैं। वैकल्पिक रूप से, यह मानते हुए कि धारा 26-ए के तहत नियम बनाने वाले प्राधिकरण को दिया गया जनादेश विचाराधीन नियमों को बनाने के लिए अधिकृत करने के लिए पर्याप्त आयाम का है, तब भी, उन्हें अधिकार से परे माना जाना चाहिए, क्योंकि वे सामान्य कानून को निरस्त करने और अटॉर्नी अधिनियम की धारा 2 को निरस्त करने का प्रभाव रखते हैं, जो किसी व्यक्ति को एक एजेंट के माध्यम से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है, और यह कि

एक विधायी कार्य होने के नाते नियम बनाने वाले प्राधिकरण को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है, और धारा 26-ए, यदि इसे किसी बाहरी प्राधिकरण को ऐसी शक्ति प्रदान करने के रूप में माना जाना है, तो इसे अपने विधायी कार्य के विधायिका द्वारा एक असंवैधानिक प्रतिनिधिमंडल का गठन करने के रूप में निरस्त किया जाना चाहिए।
इन विवादों की शुद्धता पर अब विचार किया जाना चाहिए।

इंग्लैंड के कानून के अनुसार-और वह भी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत कानून है "प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, उसे किसी भी उद्देश्य के लिए एक एजेंट नियुक्त करने का अधिकार है, और वह ऐसा तब कर सकता है जब वह किसी वैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहा हो जब वह किसी अन्य अधिकार का प्रयोग कर रहा हो।" पर स्टर्लिंग, जे. जैक्सन एंड कंपनी बनाम नैपरः इन री श्मिड्ट्स ट्रेड मार्क (1)। यह नियम कुछ प्रसिद्ध अपवादों के अधीन है जब किया जाने वाला कार्य व्यक्तिगत रूप से होता है, या किसी सार्वजनिक कार्यालय से जुड़ा होता है, या किसी ऐसे कार्यालय से जुड़ा होता है जिसमें प्रत्ययी दायित्व शामिल होते हैं। लेकिन इस तरह के अपवादों के अलावा, कानून अच्छी तरह से तय है कि जो कुछ भी एक व्यक्ति खुद कर सकता है, वह एक एजेंट के माध्यम से कर सकता है। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "सामान्य कानून में, जब कोई व्यक्ति दूसरे को अपने लिए हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करता है, तो हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर होता है जो इसे अधिकृत करता है।" प्रति ब्लैकबर्न, जे. द क्वीन v बनाम जस्टीसेस ऑफ केंट में (1)। इसलिए अपीलार्थी अपने इस तर्क में सही है कि जब तक कि कानून स्वयं अन्यथा अधिनियमित नहीं करता है, एक आवेदन जिस पर एक भागीदार को हस्ताक्षर करना है, क्रम में और वैध होगा, यदि यह उसके अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित है। फिर सवाल यह है कि क्या अधिनियम में कुछ ऐसा है, जिसके लिए आवश्यक है कि धारा 26-ए के तहत एक आवेदन पर पक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
धारा 26-ए इस प्रकार हैः
"(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और आयकर या अति-कर से संबंधित तत्काल लागू किसी अन्य अधिनियम के पंजीकरण के लिए भागीदारों के व्यक्तिगत शेयरों को निर्दिष्ट करने वाले साझेदारी के साधन के तहत गठित किसी भी फर्म की ओर से आयकर अधिकारी को आवेदन किया जा सकता है।

2) आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, और ऐसे समय पर और इसमें ऐसे विवरण होंगे और ऐसे रूप में होंगे, और ऐसी तरीके से सत्यापित किया जाएगा, जो निर्धारित किया जाए; और आयकर अधिकारी द्वारा इस पर ऐसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी जो निर्धारित की जाए।

इस धारा में यह प्रावधान नहीं है कि पंजीकरण के लिए आवेदन पर भागीदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, और यह वही है जो अपीलार्थी के इस तर्क का आधार बनता है कि सामान्य कानून के तहत और वकील की शक्तियां अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी व्यक्ति को किसी एजेंट के माध्यम से कार्य करने का जो अधिकार है, उसे धारा द्वारा छीन या संक्षिप्त नहीं किया गया है। वह निर्माण के निम्नलिखित नियमों पर अपने तर्क के समर्थन में निर्भर करता हैः
(1) कानून जो किसी विषय के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, यदि संभव हो तो उनकी व्याख्या की जानी चाहिए ताकि ऐसे अधिकारों का सम्मान किया जा सके। [क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल के माध्यम से, 10 वां संस्करण, पृष्ठ 285; क़ानून पर क्रेज़, 5 वां संस्करण, पृष्ठ 111 से 114)। इस प्रकार लॉर्ड जस्टिस बोवेन ने मैन्सफील्ड बनाम मैन्सफील्ड (1) में कानून का उल्लेख किया है।
"क़ानूनों के निर्माण में, आपको उन शब्दों का अर्थ इस तरह से नहीं लगाना चाहिए ताकि वे अधिकार छीन लिए जा सकें जो क़ानून के पारित होने से पहले से मौजूद थे, जब तक कि आपके पास स्पष्ट शब्द न हों जो इंगित करते हैं कि विधायिका का इरादा ऐसा था।
(2) स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा के अभाव में, मौजूदा कानून को बदलने का इरादा विधायिका पर नहीं लगाया जाना चाहिए। (कानून पर क्रेज़, 5 वां संस्करण, पृष्ठ 114 और 115)
(3) कानून निहितार्थ द्वारा किसी क़ानून को निरस्त करने के पक्ष में नहीं है, और इसलिए बाद के क़ानून को स्पष्ट शब्दों या आवश्यक निहितार्थ के बिना पहले वाले क़ानून को निरस्त करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। (क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल के माध्यम से, 10 वां संस्करण, पृष्ठ 170; क़ानून पर क्रेज़, 5 वां संस्करण, पृष्ठ 337)।
"यदि संभव हो तो", जे. फारवेल ने कहा, "यह मेरा कर्तव्य है कि इस धारा को पहले के अधिनियम के निहित निरसन को प्रभावित न करने के रूप में पढ़ें": री चांस (9)।
"जब तक दो अधिनियम एक-दूसरे के लिए इतने स्पष्ट रूप से प्रतिकूल नहीं हैं, तब तक दोनों को एक ही समय में प्रभाव नहीं दिया जा सकता है, एक निरसन निहित नहीं होगा।" प्रति ए. एल. स्मिथ, जे. कुटनेर बनाम पिकलिपा (8) में।

इन सिद्धांतों के आलोक में, यह तर्क दिया जाता है कि धारा 26-ए का वास्तविक दायरा यह है कि यह एक भागीदार को फर्म को पंजीकृत करने का अधिकार प्रदान

करता है, और इसके प्रयोग की कार्यप्रणाली को मौजूदा कानून द्वारा विनियमित करने के लिए छोड़ देता है, और इसलिए, किसी व्यक्ति के अपने एजेंट के माध्यम से कार्य करने के अधिकार के बारे में सामान्य कानून में परिवर्तन करने या अटॉर्नी अधिनियम की धारा 2 को निरस्त करने का इरादा दिखाने से दूर, धारा इसके कार्यान्वयन के लिए उनके निरंतर संचालन पर निर्भर करती है।
अब, निर्माण के नियम जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है, वे अच्छी तरह से स्थापित हैं। लेकिन फिर, इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वे केवल विधानमंडल के सच्चे इरादे का पता लगाने में सहायक हैं जैसा कि क़ानून में व्यक्त किया गया है, और अंततः सवाल यह है कि इस संदर्भ में अधिनियम के शब्दों का क्या अर्थ है? अपीलार्थी द्वारा उद्धृत "क़ानूनों के निर्माण", 1940 संस्करण, पृष्ठ 454 पर क्रॉफर्ड के निम्नलिखित अंश को इस संबंध में उपयोगी रूप से संदर्भित किया जा सकता हैः

"किसी क़ानून को सख्त या उदार निर्माण के अधीन क्यों किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो? एकमात्र उत्तर जो संभवतः सही हो सकता है वह यह है कि उपयोग किए गए निर्माण का प्रकार विधायी इरादे को प्रभाव देता है। विधायी इरादे को प्रभावी बनाने के लिए कभी-कभी एक उदार निर्माण का उपयोग किया जाना चाहिए, और कभी-कभी इस तरह का निर्माण विधायिका के इरादे को विफल कर देगा। यदि निर्माण के नियम के संबंध में यह उचित अवधारणा है जिसका पालन किया जाना चाहिए, तो एक सख्त या उदार निर्माण केवल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विधायी अर्थ को व्यक्त करने के लिए एक क़ानून का दायरा बढ़ाया या प्रतिबंधित किया जाता है। यदि यह सख्त और उदार निर्माण प्रदान करने के लिए उचित स्थिति है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें शामिल क़ानून दंडात्मक, आपराधिक, उपचारात्मक या सामान्य अधिकार का अपमान था, क्योंकि इस वर्गीकरण पर आधारित भेद का तब कोई मतलब नहीं होगा।
सही स्थिति होने के कारण, सवाल यह है कि क्या इसकी सही व्याख्या के आधार पर, क़ानून का उद्देश्य यह था कि धारा 26-ए के तहत एक आवेदन पर भागीदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, या क्या उस पर उसकी ओर से उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

यह निर्णय लेने के लिए, 1956 में हमें न केवल धारा 26-ए की भाषा, बल्कि विधान के स्वरूप, अधिनियम की योजना और धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार की प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए। अधिनियम, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, आय-कर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए है। इस तरह के क़ानून पर लागू होने वाले निर्माण के नियम को लॉर्ड हर्शल ने बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाम वाग्लियानो (1) में कहा हैः

"मुझे लगता है कि सबसे पहले कानून की भाषा की जांच करना, और यह पूछना कि इसका स्वाभाविक अर्थ क्या है, जो कानून की पिछली स्थिति से प्राप्त किसी भी विचार से अप्रभावित है, और यह पूछने के साथ शुरू नहीं करना कि कानून पहले कैसे खड़ा था, और फिर, यह मानते हुए कि यह शायद "इसे अपरिवर्तित छोड़ने का इरादा था।"

इसलिए हमें भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों को अपने आप में एक पूर्ण और उसमें निपटाए गए मामलों की संपूर्ण संहिता बनाने के रूप में समझना चाहिए, और यह पता लगाना चाहिए कि उनका वास्तविक दायरा क्या है।

फिर अधिनियम के प्रावधानों की ओर मुड़ते हुए, कृषि आयकर आयुक्त बनाम केशव चंद्र मंडल (9) मामले में इस न्यायालय के फैसले से उनके वास्तविक महत्व पर काफी प्रकाश डाला जाता है। वहां, सवाल यह था कि बंगाल कृषि आयकर अधिनियम, 1944 के तहत बनाए गए नियम 11 का अर्थ फॉर्म संख्या 5 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें यह आवश्यक था कि वापसी में घोषणा पर "किसी व्यक्ति के मामले में, व्यक्ति द्वारा स्वयं" हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इस न्यायालय द्वारा कानून के प्रावधानों की समीक्षा पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधानमंडल का इरादा, जैसा कि उसमें व्यक्त किया गया है, सामान्य कानून नियम को बाहर करना था, जो कि प्रति अन्य पहलू के अनुसार है, और वैध होने की घोषणा पर निर्धारिती द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया जाता है कि कृषि आय-कर आयुक्त बनाम केशव चंद्र मंडल (9) केवल नियम संख्या 11 की व्याख्या पर निर्णय था और इसकी वैधता पर नहीं, और यह सवाल कि क्या नियम अधिकार से बाहर था या नहीं, मुद्दे में नहीं था।

ऐसा ही है, लेकिन वर्तमान विवाद के निर्णय की भौतिकता इस बात में निहित है कि व्यक्तिगत हस्ताक्षर की आवश्यकता के रूप में नियम 11 पर जो व्याख्या की गई थी, वह इस निष्कर्ष पर आधारित थी कि यह न्यायालय बंगाल कृषि आय-कर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने पर पहुंचा था कि विधायिका का इरादा इस विषय पर सामान्य कानून के नियम को बाहर करना था। अब, कृषि आय-कर आयुक्त बनाम केशव चंद्र मंडल (1) में जिन बंगाल अधिनियम के प्रावधानों को उपरोक्त इरादे का संकेत माना गया था, वे भारतीय आय-कर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में समान हैं, और वास्तव में, उन पर आधारित हैं, और इसलिए बाद वाले को इस विषय पर सामान्य कानून के नियम को त्यागने के इरादे को व्यक्त करने के रूप में समझना तर्कसंगत होगा।

बंगाल कृषि आय-कर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर अब ध्यान दिया जा सकता है। बंगाल अधिनियम की धारा 25 (1) में प्रावधान है कि यदि आयकर अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि किया गया विवरणी सही और पूर्ण है, तो वह निर्धारिती से आयकर कार्यालय में उपस्थित होने या कोई सबूत पेश करने या पेश करने के लिए कह सकता है, जिस पर वह भरोसा कर सकता है। यह भारतीय

आयकर अधिनियम की धारा 23 (2) के अनुरूप है। इस धारा के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें निर्धारिती द्वारा अपने एजेंट के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान है, एक ऐसा प्रावधान जो पूरी तरह से अनावश्यक होता यदि सामान्य कानून लागू करने का इरादा होता। बंगाल अधिनियम की धारा 35 और 36 में इस बात के प्रावधान हैं कि कौन निर्धारिती का प्रतिनिधित्व कर सकता है और कौन सी कार्यवाही में वे भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 61 का पालन करते हैं और अपने आप में एक पूर्ण संहिता बनाते हैं। फिर, बंगाल अधिनियम और भारतीय आयकर अधिनियम दोनों में यह प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधान अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 के प्रावधान जो यह अधिनियमित करते हैं कि पक्ष मान्यता प्राप्त एजेंटों के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, उनमें से नहीं हैं। चर्चा को संक्षिप्त करने के लिए, बंगाल अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव को कृषि आयकर आयुक्त बनाम केशव चंद्र मंडल (1) में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।
'चिन्ह' शब्द की परिभाषा को एक अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर सहित, एक अभिकर्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए धारा 25 के तहत और एक अभिकर्ता द्वारा उपस्थिति के लिए धारा 35 और 58 के तहत अनुमति और गवाहों की उपस्थिति और परीक्षा, दस्तावेजों के उत्पादन और परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने और धारा 41 और 60 के तहत नोटिसों की सेवा से संबंधित उस संहिता के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से अपनाते हुए वापसी के हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए अभिवचनों के हस्ताक्षर और सत्यापन से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करने वाले अधिनियम में किसी भी प्रावधान को हटाना पूरी तरह से महत्वहीन नहीं माना जा सकता है।
यह तर्क भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के लिए समान बल के साथ लागू होता है, और प्रतिवादी के इस तर्क का समर्थन करने के लिए बहुत दूर जाता है कि सामान्य कानून अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू होने का इरादा नहीं है।
इस प्रश्न के निर्धारण के लिए एक अन्य कारक सामग्री धारा 26-ए द्वारा प्रदत्त अधिकार की प्रकृति है। इंग्लैंड के सामान्य कानून के तहत, एक फर्म एक न्यायिक व्यक्ति नहीं है, फर्म का नाम केवल इसे गठित करने वाले विभिन्न भागीदारों को नामित करने के लिए एक समग्र अभिव्यक्ति है। लेकिन, जैसा कि इस न्यायालय ने दुलीचंद लक्ष्मीनारायण बनाम आयकर आयुक्त, नागपुर (9) मामले में बताया है, इस अवधारणा में कानूनों द्वारा प्रवेश किया गया है, और फर्मों को उन कानूनों के उद्देश्य के लिए अलग-अलग संस्थाओं के रूप में माना गया है। उन कानूनों में से एक भारतीय आयकर अधिनियम है, जो फर्म को कराधान के उद्देश्यों के लिए एक इकाई के रूप में मानता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 3 के तहत एक फर्म की कुल आय पर शुल्क लगाया जाता है, जिसमें भागीदारों की स्थिति खराब होती है, और तदनुसार अधिनियम की धारा 23 के तहत, मूल्यांकन फर्म पर उसके कुल

लाभ पर होगा। धारा 23 (5) अधिनियम के तहत पंजीकृत फर्मों के मामले में इसके लिए एक अपवाद लागू करती है, और यह प्रदान करती है कि,
(क) फर्म द्वारा स्वयं देय राशि का निर्धारण नहीं किया जाएगा, लेकिन फर्म के प्रत्येक भागीदार की कुल आय, जिसमें उसकी आय का उसका हिस्सा, पिछले वर्ष के लाभ और लाभ शामिल हैं, का निर्धारण किया जाएगा और आयुक्त के आधार पर उसके द्वारा देय राशि का निर्धारण किया जाएगा।

इस प्रकार, यदि कोई फर्म पंजीकृत है, तो यह कराधान के उद्देश्यों के लिए एक इकाई नहीं रह जाती है और इसके द्वारा अर्जित लाभ को साझेदारी के सामान्य कानून के अनुसार, व्यक्तिगत भागीदारों द्वारा उनके शेयरों के अनुसार अर्जित किया जाता है, और उन पर लाभ के अपने हिस्से सहित उनकी व्यक्तिगत आय पर कर लगाया जाता है। इस प्रावधान के फायदे स्पष्ट हैं। प्रभार्य कर की दर उच्च स्तर पर आय के लिए प्रदान किए गए उच्च पैमाने पर नहीं होगी, बल्कि निचले स्तर पर होगी जिस पर व्यक्तिगत भागीदार की आय प्रभार्य है। इस प्रकार, पंजीकरण भागीदारों को एक ऐसा लाभ प्रदान करता है जिसका वे हकदार नहीं होते, लेकिन धारा 26-ए के लिए, और ऐसा अधिकार क़ानून का एक हिस्सा होने के नाते, केवल उस क़ानून के अनुसार दावा किया जा सकता है जो इसे प्रदान करता है, और एक व्यक्ति जो धारा 26-ए के तहत राहत चाहता है, उसे इसके लाभ का दावा करने से पहले खुद को इसकी शर्तों के भीतर सख्ती से लाना होगा। दूसरे शब्दों में, अधिकार पूरी तरह से क़ानून की शर्तों द्वारा विनियमित होता है, और अन्य कानूनों के संदर्भ में उन शर्तों में जोड़ने के लिए इस तरह के अधिकार के चरित्र के लिए यह प्रतिकूल होगा। कानून को उन शर्तों के संबंध में संपूर्ण माना जाना चाहिए जिनके तहत इसका दावा किया जा सकता है।
इस प्रकार, विधान के स्वरूप, कानून की योजना और धारा 26-ए द्वारा प्रदत्त अधिकार की प्रकृति के संदर्भ में प्रश्न पर विचार करते हुए, यह निष्कर्ष अटूट है कि सामान्य कानून के नियमों को बचाने का इरादा नहीं था, और उस धारा के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने का अधिकार विशेष रूप से उसमें निर्धारित निर्देशों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है। यदि यह सही निर्माण है, तो नियम बनाने वाले प्राधिकरण को नियम बनाने के लिए अधिकृत करने में कि धारा 26-ए के तहत पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है, और कब और कैसे, क़ानून ने केवल उस प्राधिकरण को अपने कब्जे वाले विधान के क्षेत्र में विवरण भरने का निर्देश दिया है, और इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि नियम 2 और 6 धारा द्वारा प्रदत्त अधिदेश के भीतर हैं। इस दृष्टिकोण से, अधिनियम की धारा 59 (5) जो यह अधिनियमित करती है कि "इस धारा के तहत बनाए गए नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे, और उसके बाद प्रभावी होंगे जैसे कि इस अधिनियम में अधिनियमित किए गए हों" सीधे लागू होते हैं, और नियमों के अधिकार प्रश्न से परे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पेटेंट एजेंट्स बनाम लॉकवुड (1) में लॉर्ड

हर्शल की टिप्पणियों को देखें। फिर, अपीलार्थी का यह तर्क है कि विचाराधीन नियम 1882 के पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट VII की धारा 2 के प्रतिकूल हैं, और इसलिए वे अधिकार से परे हैं। इस निष्कर्ष के समर्थन में ऊपर दिए गए कारणों के अलावा कि सामान्य कानून का नियम धारा 26-ए द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र में काम करने का इरादा नहीं था, एक और और अधिक सम्मोहक कारण है कि इस तर्क को स्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यह है कि वास्तव में, दोनों वैधानिक प्रावधानों के बीच कोई टकराव नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट की धारा 2 के दायरे को समझने के लिए, इस विधान के इतिहास का उल्लेख करना आवश्यक है। इंग्लैंड के सामान्य कानून के तहत, एक उपकरण को निष्पादित करने का अधिकार रखने वाले एजेंट को प्रधान के नाम पर हस्ताक्षर करना होगा यदि उसे बाध्य होना है। यदि अभिकर्ता अभिकर्ता के रूप में अपने नाम से विलेख पर हस्ताक्षर करता है, तो वह व्यक्ति है जिसे दस्तावेज़ का पक्ष माना जाता है, न कि प्रधान। यह केवल एजेंट है जो विलेख को लागू कर सकता है, और यह वही है जो इस पर उत्तरदायी होगा। वीडियो इन री इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी (2); शैक बनाम एंटनी (3), हैल्सबरीज लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, तीसरा संस्करण, खंड 1, पृष्ठ 217, और एजेंसी पर बॉस्टेड, 10 वां संस्करण, पृष्ठ 93। कानून की इस स्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए, संपत्ति का परिवहन और कानून अधिनियम, 1881 (44 और 45, पीड़ित, अध्याय 41) ने धारा 46 को अधिनियमित किया, जो इस प्रकार हैः

"((क) अधिवक्ता का दाता, यदि उचित समझता है, तो शक्ति दाता के प्राधिकरण द्वारा अपने नाम और हस्ताक्षर और अपनी मुहर के साथ किसी भी आश्वासन, उपकरण या वस्तु को निष्पादित या कर सकता है, और इस प्रकार निष्पादित और किया गया प्रत्येक आश्वासन, उपकरण और वस्तु सभी उद्देश्यों के लिए कानून में उतनी ही प्रभावी होगी, जैसे कि इसे दाता के नाम और हस्ताक्षर और मुहर के साथ शक्ति दाता द्वारा निष्पादित या किया गया था।

(2) यह धारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में निष्पादित उपकरणों द्वारा बनाई गई वकील की शक्तियों पर लागू होती है।

भारतीय विधानमंडल ने तुरंत इसका अनुसरण किया और 1882 के पावर-ऑफ-अटॉर्नी अधिनियम VII को अधिनियमित किया, जिसमें अंग्रेजी अधिनियम की धारा 46 को शब्द-दर-शब्द धारा 2 में शामिल किया गया। इस धारा का उद्देश्य एक एजेंट द्वारा निष्पादित उपकरणों को प्रभावी बनाना है, लेकिन सामान्य कानून के नियम के अनुसार नहीं और अधिनियम मूल से अधिक प्रक्रियात्मक है। यह किसी व्यक्ति को एजेंटों के माध्यम से कार्य करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह अनुमान लगाता है कि अभिकर्ता के पास प्रधान की ओर से कार्य करने का अधिकार है, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा किए गए कार्यों की रक्षा करता है, लेकिन अपने नाम पर। लेकिन जहां प्रश्न प्राधिकरण के अस्तित्व या

वैधता के बारे में है, उस धारा का कोई संचालन नहीं है। इस प्रकार, दोनों अधिनियमों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पूरी तरह से अलग हैं। धारा 26-ए में कहा गया है कि एक भागीदार उस धारा के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग एक एजेंट को सौंप नहीं सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट की धारा 2 में कहा गया है कि यदि प्रतिनिधि मंडल हो सकता है और वास्तव में हो सकता है, तो इसका प्रयोग उसमें दिए गए तरीके से किया जा सकता है। तदनुसार दोनों धाराओं के बीच कोई टकराव नहीं है और निरसन का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

संक्षेप में, भारतीय आय-कर अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है जो उसमें निपटाए गए मामलों का संपूर्ण विवरण है और इसके प्रावधान सामान्य नियम से अलग होने का इरादा दर्शाते हैं। इसका इरादा फिर से यह है कि किसी फर्म को धारा 23 (5) (ए) का लाभ केवल तभी दिया जाना चाहिए जब वह उस धारा में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार धारा 26-ए के तहत पंजीकृत हो। और चूंकि उन नियमों के अनुसार आवेदन पर भागीदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी ओर से एक एजेंट द्वारा हस्ताक्षर अमान्य है। जिस दृष्टिकोण से हमने लिया है, अपीलार्थी द्वारा उठाया गया आगे का प्रश्न कि किसी कानून को निरस्त करने की शक्ति एक विधायी कार्य होने के नाते, केवल विधिवत गठित विधायिका द्वारा प्रयोग की जा सकती है, न कि किसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा, और यह कि किसी बाहरी प्राधिकरण को ऐसी शक्ति सौंपना असंवैधानिक है, निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होता है।
नतीजतन, हम विश्वनाथ शास्त्री, जे. से सहमत हैं कि नियम 2 और 6 नियम बनाने वाले प्राधिकरण की शक्तियों के अंतर्गत हैं, और लागत के साथ अपीलों को खारिज करते हैं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।